



हिमाचल में व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं पर नया सेस, होटल और निजी संस्थानों पर बढ़ेगा भार



हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में राजस्व बढ़ाने और विकास योजनाओं को आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं पर नया बिजली सेस लगाने की घोषणा की है। सरकार के फैसले के अनुसार अब होटल, निजी अस्पताल, शॉपिंग मॉल, कोचिंग संस्थान, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को बिजली की प्रति यूनिट खपत पर अतिरिक्त 1 रुपये का सेस देना होगा।

राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम से प्रदेश को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जिसका उपयोग आधारभूत ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। सरकार के अनुसार बढ़ती आर्थिक चुनौतियों और सीमित संसाधनों को देखते हुए नए राजस्व स्रोत तैयार करना जरूरी हो गया था।

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह सेस घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगा और केवल व्यावसायिक श्रेणी के बिजली कनेक्शनों पर ही लागू किया जाएगा।

धान सीजन से पहले पंजाब सरकार का बड़ा आश्वासन



16 मई 2026 : आगामी धान सीजन को लेकर सरकार ने किसानों को बिजली और सिंचाई सुविधाओं को लेकर बड़ा आश्वासन दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि धान की रोपाई के दौरान किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि खेती कार्य प्रभावित न हो। इसके साथ ही नहरों और ट्यूबवेलों के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था को भी मजबूत करने की तैयारी की जा रही है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार कृषि विभाग और बिजली विभाग मिलकर विशेष योजना पर काम कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती कम की जा सके। किसानों को तय समय के अनुसार बिजली उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं सिंचाई नहरों की सफाई और मरम्मत का कार्य भी तेज कर दिया गया है ताकि पानी की आपूर्ति में कोई बाधा न आए।

MSP और बिजली मुद्दों पर किसानों का प्रदर्शन, चंडीगढ़ बॉर्डर पर तनाव



चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर शुक्रवार को किसानों और पुलिस के बीच उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हजारों किसान पंजाब राजभवन की ओर मार्च करने निकले। किसानों का यह प्रदर्शन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, बिजली संशोधन बिल का विरोध, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर आयोजित किया गया था।

सुबह से ही मोहाली और चंडीगढ़ सीमा पर किसानों की भारी भीड़ जमा होने लगी थी। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जैसे ही किसानों ने आगे बढ़ने की

कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा।

इस दौरान कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शन के कारण चंडीगढ़ और मोहाली को जोड़ने वाले कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आम लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई वाहन घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे।

किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें लंबे समय से किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर रही हैं। उनका कहना था कि MSP की कानूनी

गारंटी किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही बिजली संशोधन बिल को किसान विरोधी बताते हुए उन्होंने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। किसानों ने यह भी कहा कि सिंचाई सुविधाओं की कमी और बढ़ती लागत के कारण खेती करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।

वहीं प्रशासन का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी हाल में शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों ने किसान नेताओं से बातचीत कर शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की।

हिमाचल में मौसम का बदला मिजाज, चंबा-कुल्लू-कांगड़ा में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों, विशेष रूप से चंबा, कुल्लू और कांगड़ा जिलों में तेज हवाओं, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में मौसम अचानक खराब हो सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में हवा की गति काफी तेज रह सकती है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से खराब मौसम के दौरान नदी-नालों तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।

चंबा, कुल्लू और कांगड़ा जिले पर्यटन के लिहाज से



बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गर्मियों के सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने होटल संचालकों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों पर यात्रा करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि बारिश और तेज हवाओं के कारण सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं।

मौसम विभाग ने यह भी बताया कि फिलहाल कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि बारिश के बाद तापमान में हल्की गिरावट देखने को

मिल सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रदेश के मैदानी और निचले इलाकों में गर्मी बढ़ने की संभावना है। कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा सकता है।

प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। बिजली विभाग और लोक निर्माण विभाग को भी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम को देखते हुए अपनी फसलों और बागवानी कार्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम और अचानक बढ़ रही प्राकृतिक गतिविधियां जलवायु परिवर्तन के संकेत भी हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेने और अनावश्यक यात्रा से बचने की जरूरत है।

प्राकृतिक खेती को नई रफ्तार, हिमाचल सरकार का एक लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य



हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 'हिम परिवार रजिस्टर' योजना के तहत एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार का मानना है कि रासायनिक खेती पर बढ़ती निर्भरता को कम कर प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाने से किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दे रही है। इसी दिशा में विभिन्न जिलों में किसानों को प्रशिक्षण देने, जागरूकता शिविर आयोजित करने और आधुनिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान अब पारंपरिक रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना को भी प्राकृतिक खेती से जोड़ा है। इसके तहत प्राकृतिक तरीके से उगाई गई फसलों की खरीद सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके। मक्की और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों की खरीद MSP पर करने के साथ-साथ सरकार किसानों को समय पर भुगतान भी उपलब्ध करा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक हजारों किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान ट्रांसफर किया जा चुका है, जिससे किसानों में भरोसा बढ़ा है।

राज्य सरकार का कहना है कि प्राकृतिक खेती केवल कृषि सुधार का कार्यक्रम नहीं बल्कि ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा बड़ा अभियान है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के कम उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी, जल स्रोत सुरक्षित रहेंगे और लोगों को स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। इसके अलावा प्राकृतिक खेती की लागत कम होने से छोटे और सीमांत किसानों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

प्रदेश के कई जिलों में प्राकृतिक खेती के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।

TruSoft

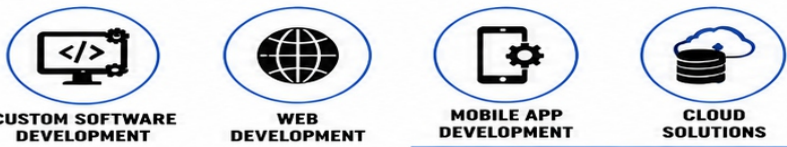
GST ACCOUNTING SOFTWARE WITH INVENTORY CONTROLS

ERP

Software that touches every part of your business.

SOFTWARE & WEB DEVELOPMENT

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”



Software for Manufacturers, Traders, Dealers/Distributors

- ALSO FOR:
- Clinical Labs

➤ Schools

➤ Drycleaners

➤ Transportation
- Pharmaceuticals

➤ Library

➤ Non Banking/Finance

➤ Weighing Scales
- Institutes

➤ Readymade Garments

➤ Dairies

➤ Cold Storage
- Hotels, Restaurants

➤ Apparels, Footwear

➤ Shuttering

➤ Sabzi Mandi

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.



PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY